an>

Title: The Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs laid a statement regarding Government Business during the week commencing the 21st November, 2016 and submissions were made by Members in regard thereto.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): With your permission Madam, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 21st of November, 2016 will consist of:-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper (*Consideration and passing of the Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2016)*
2. Consideration and passing of the Mental Health Care Bill, 2016 as passed by Rajya Sabha.
3. Introduction, consideration and passing of the following Bills:-
   (a) The Surrogacy (Regulation) Bill, 2016.
   (b) The Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Bill, 2016.
4. Consideration and passing of the HIV and AIDS (Prevention and Control) Bill, 2014, after it is passed by Rajya Sabha.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Submissions regarding the business of the House may be laid on the Table of the House.

*डॉ. **किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद)** ः महोदया, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए।

1. प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्ययन कर रहे अनूसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप में उचित बढ़ोतरी की जाए।

2. पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति में आरक्षण दिया जाए।

***श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य):** महोदया, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए ।

1. मुंबई साउथ सैंट्रल संसदीय क्षेत्र में पश्चिम रेलवे की पटरियों के आस-पास बसी झोपड़ बस्ती को रेलवे विभाग द्वारा रोज परेशान किया जाता रहा है अतः इनके पुनर्वास से संबंधित विषय और

2. देश में कई सरकारी एवं पीएसयूज़ में कार्यरत कर्मचारी वी.आर.एस. लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें काफी परेशानी हो रही है, इसमें से एक मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट भी है । अतः इन कर्मचारियों के वी.आर. एस0 से संबंधित विषय ।

***डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़)** ः महोदया, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विÂषयों का समावेश किया जाए ।

1. मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की पहाड़ियों में पूर्वुर मात्रा में उपलब्ध लौह अयस्क पर आधारित स्टील कारखाना लगाये जाने के संबंध में ।

2. मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में कृषि आधारित उद्योग के लिए मानव श्रम की पर्याप्त उपलब्धता हे और रोजगार हेतु कृÂिष पर आधारित उद्योगों को लगाए जाने की आवश्यकता है।

*श्री **भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा)** ः महोदया, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित लोक महत्व के विषयों को शामिल करकर सदन में चर्चा कराने की कृपा करें ।

1. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जानवरों की अन्ना प्रथा जिसमें जानवरों को खुला छोड़ रखा गया है, के कारण किसानों की फसलें नÂट हो रही हे, उसके निदान के लिए हर न्याय पंचायत स्तर पर एक गौ सेवा केन्द्र खोलने हेतु सदन में चर्चा कराकर इसके निदान के उपाय किए जाए ।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र के बाँदा जिले में एक गैस वाटकिंग प्लांट लगाने हेतु स्वीकृत हुआ था, उसके लिए जमीन भी जिला प्रशासन से देने की बात हो गयी थी । लेकिन उसे वहाँ से कहीं और लगाया जाने की योजना की जानकारी मिली है, जिससे इस उद्योग शून्य जनपद में गहरा आक्रोश है । कृपया इस पर सदन में चर्चा कराकर इस गैस वाटकिंग प्लांट को बाँदा में ही लगाने हेतु निर्देश देने की कृपा करें ।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) ः महोदया, लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विÂषयों को जोड़ा जायेः-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा अंतर्गत सकरी-नाटा नदी को जोड़ने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया था, जिसे ठुकरा दिया गया है । इस नदी के जुड़ने से नालंदा, शेखपुरा और नवादा की हजारों एकड़ जमीन में पटवन हो सकता है, जिससे किसानों की पैदावार पर असर पड़ सकता है । अतः सरकार की महत्वकांक्षी रीवर-लिंक योजना के अंतर्गत सकरी-नाटा नदी को जोड़ने की मैं केन्द्र सरकार से माँग करता हूँ ।

2. बिहार में मुछुआरा समुदाय अति पिछड़ा समुदाय में है, जिसे अनुसूचित जाति में जोड़े जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है। मगर अभी तक इस प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं मिली है ।

जबकि उन्हें अनुसूचित जाति में जोड़े जाने का वायदा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चुनाव के दौरान किया गया था। अतः मेरी केन्द्र सरकार से माँग है कि मछुआरा समुदाय को अनुसूचित जाति की श्रेणी में जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की जाये ।

ओश्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए ।

1. भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ गौ वंश को बचाने के लिए सरकार युद्धस्तर पर गौर अभ्यारण प्रारंभ करे ।

2. देश में विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव एक साथ कराये जाने एवं सरकार के खर्च पर चुनाव कराने पर विचार ।

*SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): The following item may be taken for discussion during the next week's Business

In Tamil Nadu, there are seven different Agro Climatic Zones suited for horticultural crops. The National Horticultural Mission covers only 22 districts out of 31 districts. The remaining nine districts may also be declared as NHM districts, so that the farmers of these districts will also get benefit of NHM.

ओश्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) ○:महोदया, निम्नलिखित विÂषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाये।

1. उत्तर बिहार के कोसी प्रमंडल के अन्तर्गत सहरसा एवं वीरपुर में राज्य सरकार का हवाई अड्डा काफी पुराना है एवं छोटा विमान का प्रचालन भी होता है, इस हवाई अड्डा का विस्तार एवं सौन्दर्यीकरण कर वाणिज्यिक सेवा शुरू करने से इस क्षेत्र को जनता को सुविधा के साथ-साथ सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी । अतः सहरसा एवं वीरपुर हवाई अड्डा का विस्तार एवं सौन्दर्यीकरण कर वाणिज्यिक सेवा शुरू करने हेतु सख्त नियम बनाया जाये ।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल के जिला मुख्यालय में रेलवे का फाटक है एवं इस फाटक से सुपौल जिला के 75 प्रतिशत लोगों का आवागमन अपने दैनिक जरूरत की पूर्ति के लिए लगा रहता है, एवं इसी फाटक से दो राजपथ क्रमशः सुपौल से रानीगंज वाया पिपरा, त्रिवेणीगंज एवं सुपौल से भपटियाही वाया किशनपुर गुजरती है तथा इस फाटक के बगल में सुपौल का बस अड्डा भी है, जिसके परिणामस्वरूप भयंकर जाम लगा रहता है, ऐसी परिस्थिति में सुपौल के लौहिया नगर चौक से पिपरा एवं किशनगंज जाने वाली सड़क पर सड़क उपरी पुल आवश्यक है । अतः सुपौल के लौहिया नगर चौक से पिपरा एवं किशनगंज जाने वाली सड़क पर सड़क उपरि पुल बनाने हेतु सख्त नियम बनाया जाये।

ओश्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल)○: महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विÂषयों को शामिल किया जायः-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र मावल में पनवेल, खालापुर स्टेशन से लगभग एक लाख नागरिक रोज मुंबई तक लोकर ट्रेन से आवागमन करते हैं अतः इन स्टेशंस पर एक्सीलेटर लगाये जाने की व्यवस्था करने और

2. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी की भारी परेशानी है जबकि इन स्टेशन से प्रतिदिन लाखों लोग आवागमन करते हैं और इन्हें पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पाता है । अतः इन स्टेशन पर आर.ओ. वाटर व्यवस्था किए जाने से संबंधित विÂषय को शामिल किया जाए।

*DR. UDIT RAJ (NORTH WEST DELHI): Since October 16, 2013, a black African quota has been passed in South Africa, under which franchises will have to field at least one player from the country's majority race group, and amateur teams, two. Those franchises that have more than one black African in 70 per cent of their matches will be reimbursed an amount equivalent to the average contract cost of the qualified players. This incentive based reservation was implemented after it was observed that most black African players give up the game between the under-19 and provincial level, at an age at which, if they are not contracted, will need to find jobs. The report also revealed that when black African players do get into the system, they are often further sidelined. Only two black African players turned out in more than 80 per cent of their franchise's games last season and when they did, they bowled less overs and batted lower down than players of other races. A similar incentive based scheme should be brought into all sports supported either by the Government of India, State Governments or PSUs to increase participation of SC/STs and OBCs in all sports, including cricket.

The Delhi Development Authority acquired land at Narela in my Constituency in 1986 to build a sub-city, but the purpose for which it was acquired has yet to be achieved. Thousands of flats were to be built on this land; some have been completed while most are still under construction. The flats that have been completed are also not occupied as residents do not want to shift to them due to lack of transportation facilities. A survey has also been completed to lay down a metro rail in this area, but no further action has been taken. I request that Minister of Urban Development immediately look into this issue, and expedite completion of the Narela sub city which has been pending since 1986.

...(*Interruptions*)